C761

Total Pages : 4 Roll No. ....

CRTI-103/DRTI-103

Judiciary and Important Legislatures Effecting RTI

आरटीआई को प्रभावित करने वाली न्यायपालिका और महत्त्वपूर्ण विधायिका

Certificate/Diploma in Right to Information (CRTI/DRTI)

2nd Semester Examination, 2022 (June)

Time : 2 Hours] **Max. Marks : 100**

Note : This paper is of Hundred (100) marks divided into two (02) Sections A and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र सौ (100) अंकों का है जो दो (02) खण्डों क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

SECTION–A/(खण्ड-क)

(Long Answer Type Questions)/(दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न)

Note : Section 'A' contains Five (05) long answer type questions of Twenty six (26) marks each. Learners are required to answer any Two (02) questions only.

(2×26=52)

नोट : खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए छब्बीस (26) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. 'Right to know' is also included under the Article 19(1) (a) of the Indian Constitution. Write detail comment.

'जानने का अधिकार' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भी शामिल है। विस्तार से टिप्पणी लिखें।

2. Write an essay on observation of courts regarding proactive disclosure under RTI Act.

आरटीआई अधिनियम के तहत सक्रिय प्रकटीकरण के संबंध में न्यायालयों के अवलोकन पर एक निबंध लिखें।

3. Can too much transparency affect independence of judiciary? Give a critical analysis.

क्या बहुत अधिक पारदर्शिता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है? आलोचनात्मक विश्लेषण दीजिए।

4. The main objective of RTI Act is to ensure transparency and accountability in the working of the government and functioning of public authorities. Discuss the various decisions of the CIC on the above statement.

आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उपरोक्त कथन पर सीआईसी के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा कीजिए।

5. What are the objectives behind enacting Whistle Blowers Protection Act, 2011?

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 को अधिनियमित करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं?

SECTION–B/(खण्ड-ख)

(Short Answer Type Questions)/(लघु उत्तरों वाले प्रश्न)

Note : Section 'B' contains Eight (08) short answer type questions of Twelve (12) marks each. Learners are required to answer any Four (04) questions only.

(4×12=48)

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए बारह (12) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Give a brief note on need of transparency in a country like India.

भारत जैसे देश में पारदर्शिता की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

2. Discuss the Whistle Blowers role in protection of RTI activists.

आरटीआई कार्यकर्ताओं के संरक्षण में व्हिसल ब्लोऊर की भूमिका की विवेचना कीजिए।

3. What are the provisions of Section 7of the RTI Act, 2005.

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7 के प्रावधान क्या हैं?

4. Briefly mention various sections of the Public Records Act, 1993.

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं का संक्षेप में उल्लेख करें।

5. What are the grounds of restriction on the freedom of speech and expression?

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार क्या हैं?

6. What are the guidelines for digital publication of proactive disclosure under section 4 of RTI Act?

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण के डिजिटल प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश क्या हैं?

7. Which article of Indian Constitution guaranteed equality before the law or the equal protection of the laws to all its citizens? Explain.

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने अपने सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी दी है? समझाइए।

8. Which landmark court case formed the basis of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013? Explain the guidelines laid down by the court in that landmark case.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का आधार किस ऐतिहासिक अदालती मामले ने बनाया? उस ऐतिहासिक मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की व्याख्या करें।